राजस्थान बजट 2017–18

—नेसार अहमद

मुख्यमंत्री महोदया ने वर्ष 2017–18 के लिये बजट पेश करते हुए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। पर्यटन, संस्कृति, धरोहरों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, मज़ारों, मदरसों, गुरूद्वारों, मन्दिरों सहित तमाम घोषणाएं करते हुए, मुख्यमंत्री ने समाज के सभी वर्गों – युवाओं, किसानों, महिलाओं तथा छात्रों को संबोधित किया। वर्ष 2017–18 के लिये कुल 1.66 लाख करोड़ रूपये का बजट पेश करते हुए सरकार ने 13528 करोड़ रूपये के राजस्व घाटा तथा 24753 करोड़ रूपये के राजकोषीय घाटा होने का अनुमान लगाया है।

बजट में जहां युवाओं के लिये रोजगार तथा कौशल निर्माण पर जोर दिया गया है, वहीं नोटबंदी का ज़िक्र तक नहीं किया गया। लेकिन नोटबंदी का असर इस बजट पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। चालु वर्ष में राज्य की कुल राजस्व प्राप्तीयों में 7 हजार करोड़ रूपये की कमी होने का अनुमान है और यही कारण है कि चालु वर्ष के राजस्व घाटे में लगभग 8000 करोड़ रूपये की बढ़ोतरी हुई है।

इसी तरह मुख्यमंत्री महोदया ने बजट भाषण में उद्योगों, रोजगार तथा कौशल विकास की चर्चा करते हुए कहीं भी रिसर्जेन्ट राजस्थान तथा उसमें हुए समझौतों पर कोई चर्चा नहीं की।

अगर बात आगामी वर्ष के आंकड़ों की करें तो सरकार ने 130 हजार करोड़ रूपये की कुल राजस्व आय का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से

लगभग 12 प्रतिशत अधिक है। परन्तु पिछले वर्षों के रूझानों को देखें तो संशोधित अनुमान तथा वास्तविक आय हमेशा बजट अनुमान से कम रहे हैं।

अगर सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, स्वच्छता एवं पेयजल, अनु. जाति, जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, श्रम कल्याण, सामाजिक कल्याण एवं पोषण तथा ग्रामिण विकास के बजट में कुल मिलाकर पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से मात्र 5408 करोड़ रूपये की बढ़ोतरी की गई है। अगर बजट अनुमानों से तुलना करें तो इन क्षेत्रों में कुल आवंटन में मात्र 350 करोड़ रूपये बढ़ोतरी हुई है। बजट अनुमान की तुलना में स्वास्थ्य पर मात्र 213 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है तथा शिक्षा पर 2226 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। स्मार्ट सिटी की तमाम घोषणाओं के बावजूद शहरी विकास का बजट पिछले वर्ष की तुलना में 300 करोड़ रूपये कम हुआ है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सामाजिक समरसता की बात करने के बावजूद सरकार ने अनु. जाति, जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण (अल्पसंख्यक सहित) के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। बजट भाषण में 5000 से अधिक आबादी वाले गांवो को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की गई है, लेकिन ग्रामिण विकास का कुल बजट भी पिछले वर्ष के बजट अनुमान के बराबर ही रखा गया है। कृषि तथा संबद्व क्षेत्र में भी बजट बढ़ोतरी नहीं हुई है तथा यह 6159 करोड़ रूपये है जो पिछले वर्ष के लगभग समान है। सिंचाई के बजट में अवश्य कोई 500 करोड़ रूपये की वृद्वि हुई है।

अगर बात मुख्य केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की करें तो सर्व शिक्षा अभियान का बजट 4550 करोड़ रूपये से नहीं बढ़ा है, जबकि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का

बजट आधा हो गया है। मध्यान्ह भोजन का बजट भी स्थिर रहा है जबकि राष्ट्रीय समेकित बाल संरक्षण योजना में कटौती की गई है। हालांकि बजट भाषण में नये बाल गृह खोले जाने की घोषणा हुई।

राज्य में एकल नारी, वृध्द्ध एवं विकलांग जनों के लिये पेंशन की योजनाएं संचालित हैं। इस बजट में सरकार ने विधवा पेंशन की राशि को बढ़ा दिया है तथा सभी विकलांगजनों, के पेंशन को भी 750 रूपये प्रति माह कर दिया है। इसके साथ ही सरकार वृद्धजनों के पेंशन में भी वृद्वि कर सकती थी जो नहीं की गयी है।

राजस्थान सरकार की योजनाओं की बात करें तो मुख्यमंत्री मुफ्त दवा एवं मुफ्त जांच योजनाओं के बजट में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष शुरू किये गये मुख्यमंत्री राजश्री योजना जिसके अन्तर्गत बच्चियों के जन्म पर 50000 रूपये की राशि दी जाती है, के लिये 196 करोड़ रूपये रखे गये हैं।

खनन क्षेत्रों में 500 करोड़ रूपये स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर खर्च होंगे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि अगर यह अतिरिक्त राशि है तो यह खर्च किस विभाग/संस्था के माध्यम से होगा। कोटा तथा जोधपुर में सिलीकोसिस चिकित्सा केन्द्र खोलना अवश्य स्वागत योग्य कदम है परन्तु ऐसे केन्द्रों की आवश्यक्ता राज्य के अधिकांश जिलों को है।

महिलाओं के लिये चिराली योजना की घोषणा की गई है, जो मुख्यतः एक जागरूकता कार्यक्रम है। 1000 महिला दूग्ध केन्द्र, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 5000 रूपये तथा छात्रावास में रहने वाले छात्र/छात्राओं को साइकिल दी जायेगी।

कुल मिलाकर सरकार ने इस बजट में जहां समाज के सभी वर्गो को खुश करने के प्रयास किया है वहीं बजट का आर्थिक पक्ष बहुत मज़बुत नहीं दिखता। हलांकि आने वाले वर्ष में राजस्व घाटे को न्युनतम रखने तथा राजकोषीय घाटे को 2.99 प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा गया है, परन्तु वर्तमान वित्तिय वर्ष में भी राजकोषीय घाटे 3.37 प्रतिशत रहने का अनुमान है। सरकार की कुल देनदारीयां भी इस वर्ष 2.53 लाख करोड़ है जो राज्य के सकल धरैलू उत्पाद का 33.79 प्रतिशत है जबकि यह वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 25 प्रतिशत तक ही होना चाहिये। वर्ष 2017–18 में सरकार की कुल देनदारीयां 2.78 करोड़ तक हो जायेंगी। जाहिर है इससे सरकार का ब्याज पर खर्च भी बढ़कर 19626 करोड़ रूपये हो जाने का अनुमान है, जो इस वर्ष 17734 करोड़ पर रूपये है।

ऐसे में सरकार को अपने वित्तिय प्रबंधन को चुस्त रखने की जरूरत है जिससे लोक कल्याणकारी घोषणाओं को पूरा करते हुए राज्य की वित्तिय स्थति को भी सुदृढ रखा जा सके।

नेसार अहमद